Threat By Japan regarding Anti-dumping Duties

*172. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of COMMERCE be pelased to state:

(a) whether Japan has threatened India regarding imposition of anti-dumping duties on certain products;

(b) if so, which are the products; and

(c) whether that is a violation of any of the provisions of W.T.O regarding anti-dumping?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI RAMAKRISHNA HEGDE): (a) and (b) No, Sir. Japan has not threatened India regarding imposition of Anti-Dumping Duties. However, Japan has through its embassy in India sent a Note Verbale to the Government wherein, it has sought clarification on the preliminary findings in the Anti-dumping investigation concerning Industrial Sewing Machine needles against Japan, Korea, Germany, China and Czech Republic.

(c) No provision of the Multilateral Trade Agreements has been violated regarding Anti-Dumping by India, Anti-dumping proceedings in India are in accordance with the Section 9(a), (b) and (c) of the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time and the Rules made thereunder, which are in accordance with the WTO agreement on Anti-dumping.

भिक्षावृत्ति की समस्या

*173. **श्रीमती सरोज दुबे:** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि देश के विभिन्न महानगरीय शहरों में बच्चों से भीख मंगवाने का धन्धा संगठित गिरोहों के द्वारा संचालित होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पर्दे के पीछे काम करने वाले इन गिरोहों को पकड़ने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ग) गत छः महीनों में ऐसे गिरोहों के कितने व्यक्तियों को पकड़ा गया है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) यद्यपि देश के विभिन्न महानगरीय शहरों में बच्चों से भीख मंगवाने का धंधा करने के लिए बाध्य करने वाले संगठित गिरोहों के विद्यमान होने के बारे में समाचार पत्रों में समय-समय पर रिपोर्टें प्रकाश में आई हैं तथापि, ऐसे संगठित गिरोहों के विद्यमान होने की पुष्टि करने के लिए सरकार के पास कोई प्रमाणित रिपोर्ट नहीं है।

(ख) सरकार ने बच्चों द्वारा भीख मांगने सहित भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए अनेक उपाय किए हैं, जिनमें कुछ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए अधिनियमन, किशोर न्याय अधिनियम, 1986 में भिक्षावृत्ति रोकने के लिए प्रावधान, तथा राज्य सरकारें तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भिक्षु गृहों की स्थापना शामिल है।

(ग) और (घ) यह सूचना मंत्रालय द्वारा नहीं रखी जाती है क्योंकि यह विषय राज्यों से उनके अपने-अपने विधानों के अंतर्गत संबंधित है।

Minority Status For Hindus

*174. PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA:
SHRI RAGHAVJI:

Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the National Commission for the Minorities has asked Government to grant minority status for Hindus in some of the States;

(b) if so, which are these states and the reasons advance therefor by the Commission; and

(c) what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRIAMTI MANEKA GANDHI): (a) and (b) Yes, Sir. The National Commission for Minorities has sent its recommendation